भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1428

(09 **दिसम्बर**, 2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए)**

मिशन अमृत सरोवर

1428. **श्री मुरारी लाल मीना:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत अब तक देश में राज्य-वार कितने अमृत सरोवरों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार कराया गया है;

(ख) क्या इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार करना था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में इस मिशन के अंतर्गत कितने अमृत सरोवरों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार किया गया है;

(घ) इस मिशन के अंतर्गत दौसा जिले में कितनी झीलें बनाई गई हैं और वर्तमान में ऐसी कितनी झीलें पूरी तरह से चालू हैं; और

(ङ) क्या सरकार उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता या तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रही है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(**श्री कमलेश पासवान**)

(क): मिशन अमृत सरोवर चरण –I के अंतर्गत 04.12.2025 तक निर्मित/जीर्णोद्धार किए गए अमृत सरोवरों की राज्यवार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग): मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर (तालाब) का निर्माण/विकास करना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी ग्रामीण जिलों (दिल्ली, चंडीगढ़ एवं लक्षद्वीप को छोड़कर) को न्यूनतम 75 अमृत सरोवर विकसित करने थे और इस प्रकार पूरे देश में लगभग 50,000 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दिनांक 04.12.2025 तक मिशन अमृत सरोवर चरण–I के अंतर्गत देशभर में कुल 68,827 अमृत सरोवर निर्मित/जीर्णोद्धार किए जा चुके हैं।

राजस्थान राज्य में मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत दिनांक 04.12.2025 तक कुल 3,139 अमृत सरोवर निर्मित/पुनरूद्धार किए गए हैं।

(घ): राजस्थान के दौसा जिले में मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत 04.12.2025 तक कुल 78 *अमृत सरोवर* निर्मित/पुनरूद्धार किए गए हैं।

(ड.) यह मिशन विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिनमें राज्यों की अपनी योजनाओं तथा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), 15वें वित्त आयोग के अनुदान , प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजनाएँ यथा- वाटरशेड विकास संघटक, हर खेत को पानी आदि शामिल हैं।

मिशन अमृत सरोवर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यापक तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें मिशन अमृत सरोवर दिशानिर्देशों के माध्यम से मार्गदर्शन , पूरक परामर्श, तकनीकी कार्यशालाएँ तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संचालन संबंधी चुनौतियों का सामना किए जाने पर निरंतर सहयोग किया जाना शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने अमृत सरोवर पोर्टल विकसित किया है , जो राज्यों को प्रगति की निगरानी करने एवं स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम बनाता है। साथ ही , आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एक वाटर ऑब्ज़र्वेटरी बनाई गई है, जो पूर्ण हो चुके सरोवरों का नक्शा-आधारित विवरण प्रदान करती है , जिसमें जलभराव क्षेत्रों की मौसमी एवं मासिक जानकारी भी शामिल है। ये डिजिटल उपकरण डेटा आधारित निगरानी को सुदृढ़ करते हैं तथा पारदर्शिता बढ़ाते हैं।

अमृत सरोवरों की प्रगति की नियमित निगरानी केंद्र स्तर पर भी की जाती है , जिसमें सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने, उपयोगकर्ता समूहों की स्थापना, अजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा अमृत सरोवर स्थलों को सक्रिय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता है।

दिनांक 09.12.2025 **को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या** 1428 **के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

मिशन अमृत सरोवर चरण–I के अंतर्गत 04.12.2025 तक निर्मित/जीर्णोद्धार किए गए अमृत सरोवरों की राज्यवार संख्या		
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**निर्मित/पुनरूद्धारित अमृत सरोवरों की कुल संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	227
2	आंध्र प्रदेश	2154
3	अरुणाचल प्रदेश	778
4	असम	2963
5	बिहार	2613
6	छत्तीसगढ	2902
7	गोवा	159
8	गुजरात	2652
9	हरियाणा	2087
10	हिमाचल प्रदेश	1690
11	जम्मू और कश्मीर	1056
12	झारखंड	2047
13	कर्नाटक	4054
14	केरल	865
15	लद्दाख	100
16	मध्य प्रदेश	5825
17	महाराष्ट्र	3055
18	मणिपुर	1226
19	मेघालय	705
20	मिजोरम	1029
21	नागालैंड	255

22	ओडिशा	2367
23	पुदुचेरी	156
24	पंजाब	1453
25	राजस्थान	3139
26	सिक्किम	199
27	तमिलनाडु	2484
28	तेलंगाना	1871
29	दादरा नगर और हवेली, दमन और दीव	57
30	त्रिपुरा	682
31	उत्तराखंड	1319
32	उत्तर प्रदेश	16632
33	पश्चिम बंगाल	26
	कुल	68827